# झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

## सिविल रिट याचिका संख्या 2633/2017

मेसर्स नंद लाल पांडे, एक साझेदारी फर्म, कार्यालय -; गढ़वा रोड, रेहाला, डाक घर और थाना- रेहाला, जिला ;- पलामू , के माध्यम से;- नंद लाल पांडे, पिता- श्री सुरेंद्र पांडे, निवासी वेस्ट एंड पार्क, डाक घर- हेहल, थाना- सुखदेवनगर, जिला रांची ... याचिकाकर्ता

***बनाम***

1. झारखंड राज्य, सचिव, सड़क निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, रांची, डाक घर और थाना धुर्वा, जिला - रांची के माध्यम से।

2. इंजीनियर-इन-चीफ, पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, रांची, डाक घर और थाना धुर्वा, जिला-रांची।

3. मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, झारखंड सरकार, डाक घर और थाना धुर्वा, जिला-रांची, रांची।

4. अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, मेदिनीनगर, डाक घर और थाना - डाल्टनगंज, जिला- पलामू।

5. अधिशासी अभियंता, पथ निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, मेदिनीनगर, डाक घर और थाना.- डाल्टनगंज, जिला- पलामू

6. प्रमाण पत्र अधिकारी, डाक घर और थाना - डाल्टनगंज, जिला- पलामू

... उत्तरदाताओं

---

याचिकाकर्ता के लिए प्रतिवादी: श्री विभोर मयंक,

उत्तरदाताओं के लिए वकील: श्री देवेश कृष्ण, एससी (खान) III

---

**<u>उपस्थित</u>**

**माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी**

***अदालत द्वारा:-*** दोनों पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें बिहार और उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1914 (झारखंड राज्य द्वारा अपनाया गया) के प्रावधानों के तहत उत्तरदाता सं. 5 के आवेदन पर उत्तरदाता सं. 6 द्वारा शुरू की गई पूरी कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो 2008-09 के समझौते संख्या 4 एफ 2 और 1 एफ 2 /2011-12 के गढ़वा नगर मुरीसेमर खंड के एन एच -75 से 235 किमी में तेरकी नाला पर पुल के निर्माण और अन्य राहतों का कार्य के संबंध में कथित बकाया राशि की वसूली के लिए है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि तेरकी नाला पर कार्य के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित करने वाले सूचना के अनुसरण में; याचिकाकर्ता ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया। याचिकाकर्ता ने सुरक्षा जमा के रूप में 2,60,000/- रुपये और आगे 2,88,000/- रुपये की बयाना राशि प्रस्तुत की और काम शुरू करने के आदेश जारी होने की तारीख से काम पूरा करने का समय 12 महीने था। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि शुरू *से ही*, उत्तरदाताओं विभागों की ओर से कमियां थीं और उन्होंने याचिकाकर्ता को पुल के निर्माण के लिए साइट प्रदान नहीं करके समझौते के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन किया है, क्योंकि कई *रैयती* भूखंड थे जो हालांकि विभाग द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, लेकिन उसी के लिए मुआवजे का भुगतान ग्रामीणों को नहीं किया गया था। । मूल रूप से विचार किए गए पुल का ड्राइंग और डिजाइन दोषपूर्ण था। उत्तरदाताओं ने चालू खातों के बिलों के भुगतान में भी देरी की। फिर भी याचिकाकर्ता ने निर्धारित समय के भीतर 70% काम पूरा कर लिया, लेकिन

उत्तरदाताओं के विभाग ने याचिकाकर्ता को उसी की प्रति दिए बिना याचिकाकर्ता के समझौते को समाप्त कर दिया। याचिकाकर्ता को पता चला कि उक्त समझौते के संबंध में कथित बकाया राशि की वसूली के लिए एक प्रमाण पत्र मामला याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू किया गया है और याचिकाकर्ता ने उक्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया और उक्त प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर पता चला कि उत्तरदाता सं. 6 के समक्ष उत्तरदाता सं. 5 की मांग पर,उत्तरदाता सं. 6 ने यह सुनिश्चित किए बिना कि क्या कथित बकाया राशि सार्वजनिक मांग के दायरे में आती है, जैसा कि अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है, बिहार और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (झारखंड राज्य द्वारा अपनाया गया) है, याचिकाकर्ता को सूचना जारी करने का आदेश दिया। यह तर्क दिया जाता है कि कथित बकाया राशि जिसके लिए अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, अधिनियम की अनुसूची 1 के साथ पठित धारा 3 (6) के अर्थ के भीतर "सार्वजनिक मांग" नहीं है। इसलिए, संविदात्मक विवाद के संबंध में देय राशि की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रतिवादी की ओर से दायर आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है। इसलिए, उत्तरदाता सं. 6 ने सबसे मनमाने, सनकी और दुर्भावनापूर्ण तरीके से अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया है, उत्तरदाता सं. 5 के आवेदन पर यंत्रवत् रूप से कार्य करते हुए बिना किसी संतुष्टि को दर्ज किए कि कथित बकाया अधिनियम के अर्थ के भीतर एक सार्वजनिक मांग है। उत्तरदाता सं. 6 ने अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत भौतिक अवैधता और अनियमितता में काम किया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील **कर्नाटक राज्य बनाम श्री रामेश्वर राइस मिल्स, तीर्थाहल्ली** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं, जिसकी रिपोर्ट **(1987) 2 एससीसी 160 अनुच्छेद 9** में की गई है, जिसमें से निम्नानुसार है: -

> *"9. xxxxx xxxx xxxx शब्द "इस समझौते के किसी भी हिस्से के तहत दूसरे पक्ष को पहली पार्टी द्वारा देय या देय हो सकता है कि किसी भी राशि" शर्तों के उल्लंघन के लिए नुकसान का भुगतान करने के लिए राज्य के साथ अनुबंध करने वाली पार्टी पर देयता निर्धारित करने वाले खंड के पहले भाग के*

*साथ संयोजन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, यह इस प्रकार है कि हालांकि समझौते की शर्तों के उल्लंघन के कारण नुकसान देय हो जाता है, फिर भी वे अनुबंध के तहत देय राशि का गठन करते हैं अर्थात अनुबंध की शर्तों में से एक के तहत शर्तों के उल्लंघन के लिए नुकसान का भुगतान करने के लिए देयता लगाते हैं। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यदि समझौता उपायुक्त द्वारा मूल्यांकन की जाने वाली राशि के बजाय शर्तों के उल्लंघन के लिए नुकसान के रूप में भुगतान की जा रही एक परिसमापन राशि का प्रावधान करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्दिष्ट नुकसान अनुबंध के तहत देय धन नहीं होगा और इसलिए राजस्व वसूली अधिनियम के तहत नुकसान की वसूली नहीं की जा सकती है। निर्दिष्ट नुकसानों पर जो लागू होता है वह उन नुकसानों पर भी लागू होगा जो मूल्यांकन के बाद निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए, हम मानते हैं कि जहां तक भू-राजस्व के बकाया के रूप में नुकसान की वसूली का संबंध है, पूर्ण पीठ की राय कानून के अनुसार नहीं है।*

और प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरदाता सं. 5 को कथित रूप से देय और देय धन न तो अग्रिम है और न ही बकाया ऋण है और न ही लिखित समझौते द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई है कि राशि सार्वजनिक मांग के रूप में वसूली योग्य होगी और न ही इसे किसी कानून द्वारा घोषित किया गया है जो समय के लिए लागू है या बकाया राजस्व के रूप में वसूली योग्य है और न ही इसे किसी अधिनियमन द्वारा घोषित किया गया है अधिनियम की अनुसूची 1 के किसी अन्य खंड के तहत सार्वजनिक मांग या सार्वजनिक मांग होने के लिए तत्समय लागू होने के लिए। इसलिए, उत्तरदाता सं. 5 के दावे की वसूली के लिए प्रमाण पत्र कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील **जेजी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और एक अन्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं **(2011) 5 एससीसी 758 अनुच्छेद -19** में पारित किया गया है, जिसमें से निम्नानुसार है: -

*"19. वास्तव में यह सवाल कि क्या दूसरे पक्ष ने उल्लंघन किया है, उल्लंघन का आरोप लगाने वाली पार्टी द्वारा तय नहीं किया जा सकता है। एक अनुबंध यह प्रदान नहीं कर सकता है कि एक पक्ष यह तय करने के लिए मध्यस्थ होगा कि उसने उल्लंघन किया है या दूसरे पक्ष ने उल्लंघन किया है। और प्रस्तुत करता है कि यह एक ऐसा मामला है जहां उत्तरदाता सं. 5 जो स्वयं एक अनुबंध का एक पक्ष है, ने फैसला किया है कि याचिकाकर्ता होने के नाते दूसरे पक्ष ने समझौते का उल्लंघन किया है जो कानून में टिकाऊ नहीं है।*

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील अगली बार **बृज मोहन प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य** के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं, जो **2008 एससीसी ऑनलाइन पैट 1157** में रिपोर्ट किया गया था और उक्त निर्णय के अनुच्छेद -11 की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एक प्रमाण पत्र कार्यवाही में, दायित्व *प्रथम दृष्टया*, पूर्व निर्धारित है और कार्यवाही केवल उन पूर्व निर्धारित देयता की वसूली के लिए है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील आगे **1980 एससीसी ऑनलाइन पैट 74 अनुच्छेद -3** में रिपोर्ट किए गए **बुद्ध सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य** के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं, जिसमें से निम्नानुसार है: -

*"3. अधिनियम की धारा 1 की मद संख्या 9 के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि यदि कोई पक्ष लिखित लिखत द्वारा सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता है, तो उस मामले में यह सार्वजनिक मांग के रूप में वसूल किया जाएगा। अनुलग्नक 1 के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि नुकसान की राशि अनुबंध 1 में बिल्कुल भी उल्लिखित नहीं है। किसी भी निर्दिष्ट राशि के अभाव में, इस तरह के पैसे को आइटम नंबर 9 के तहत वसूल नहीं किया जा सकता है।*

आइटम नंबर 9 में उल्लिखित 'पैसा' शब्द का अर्थ है पार्टियों के समझौते में निर्दिष्ट धन। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नुकसान की राशि का उल्लेख अनुलग्नक 1 में नहीं किया गया है; अत वन विभाग द्वारा क्षति की राशि वसूल नहीं की जा सकती है। न तो

करार और न ही अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में वन विभाग द्वारा वहन की गई क्षति का पता लगाने के लिए किसी तंत्र का प्रावधान है। जब भी किसी धन को सार्वजनिक मांग या राजस्व के बकाया या भू-राजस्व के रूप में बकाया के रूप में वसूल किया जाता है, तो इन सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट राशि का उल्लेख किया जाता है। यदि क्षति की राशि का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका पता केवल सिविल कोर्ट द्वारा लगाया जा सकता है, न कि स्वयं वन विभाग द्वारा। और प्रस्तुत करता है कि अधिनियम की अनुसूची 1 के आइटम नंबर 9 के अनुसार, एक लिखित साधन कि सरकार को राशि का भुगतान अन्य बातों के साथ-साथ वसूली योग्य होगा क्योंकि सार्वजनिक मांग एक अनिवार्य शर्त है और इस मामले में ऐसा कोई लिखित साधन नहीं है जनता की मांग के रूप में राशि की वसूली के लिए। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के लिखित साधन के अभाव में, सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं है।

8. अंत में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील **कृष्ण नंद टंडन बनाम बिहार राज्य और अन्य** के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं, जो **1992 एससीसी ऑनलाइन पैट 181 अनुच्छेद -5** में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें से निम्नानुसार है: -

> *"5. जहां तक उपरोक्त प्रविष्टि संख्या 4 का संबंध है, यह केवल वहीं लागू होगा जहां उसमें निहित आवश्यक घोषणा किसी अधिनियमन द्वारा की गई है और इसलिए भले ही निविदा सूचना यह प्रदान करता है कि नुकसान को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है, फिर भी इसे अधिनियम के तहत प्रदान किए गए वैधानिक अर्थ के भीतर सार्वजनिक मांग के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि निविदा सूचना को एक अधिनियमन नहीं कहा जा सकता है।*

और प्रस्तुत करता है कि जहां तक अधिनियम की अनुसूची 1 में प्रविष्टि संख्या 4 का संबंध है, किसी भी अधिनियमन द्वारा उसमें निहित एक घोषणा होनी चाहिए और इसलिए, भले ही निविदा सूचना यह प्रदान करता है कि नुकसान को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है, फिर भी इसे अधिनियम के तहत प्रदान किए गए वैधानिक अर्थ के भीतर सार्वजनिक मांग के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि निविदा सूचना को एक अधिनियमन नहीं कहा जा सकता है।

9. इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस रिट याचिका में की गई प्रार्थना की अनुमति दी जाए।

10. प्रतिवादी के विद्वान वकील- राज्य याचिकाकर्ता की प्रार्थना का जोरदार विरोध करता है और **मेसर्स अजय भगत बनाम झारखंड राज्य और अन्य** के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के फैसले पर भरोसा करता है, जिसकी रिपोर्ट **2018 एससीसी ऑनलाइन झार 1202** में की गई थी, जिसमें उस मामले के तथ्यों में जब याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष इसे स्वीकार किया गया था, कि उसने कुछ अग्रिम प्राप्त किए और मांग में इस तरह के अग्रिमों की वसूली शामिल थी, समन्वय पीठ ने माना कि राशि की वसूली अधिनियम की अनुसूची 1 के आइटम नंबर 8 ए के तहत कवर की गई है। उत्तरदाता- राज्य के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि ठेकेदार प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी के बावजूद 2017 साइट पर मौजूद नहीं था, इसलिए, याचिकाकर्ता या उसके प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में सहायक अभियंता द्वारा अंतिम माप लिया गया था और उक्त माप के आधार पर, अंतिम बिल कार्यकारी अभियंता, एनएचपीसी को प्रस्तुत किया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कार्य की राशि 7,29,217/- रुपये थी जो पहले ही याचिकाकर्ता को भुगतान कर दी गई थी और याचिकाकर्ता को पहले ही 4 रुपये प्राप्त हो चुके थे। 14,364/-. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम की धारा 63 अपने आदेश की समीक्षा के लिए उत्तरदाता सं. 6 का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अच्छा उपाय था।

11. यह प्रस्तुत किया गया है कि 25,36,268/- रुपये सरकारी बकाया हैं और सार्वजनिक मांग के रूप में वसूली योग्य हैं, इस प्रकार, उत्तरदाता सं. 1 ने मांग दायर की है।

12. न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि अधिनियम की अनुसूची 1 के किस मद के तहत, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दावा किया गया धन अधिनियम की धारा 3 (6) में परिभाषित सार्वजनिक मांग है, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने अनुसूची (1) की मद संख्या 9 प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है: -

> *9. सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के एक सेवक को देय कोई भी धन, जिसके संबंध में उसी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ने एक लिखित*

*साधन [x x x x] द्वारा सहमति व्यक्त की है, कि यह सार्वजनिक मांग के रूप में वसूली योग्य होगी।*

*[स्पष्टीकरण- यह मद मद 3, 4 और 7 में विनिर्दिष्ट किसी धन या माँग पर लागू नहीं होगी।*

प्रासंगिक मद है जिसके तहत उत्तरदाता सं. 5 का दावा एक सार्वजनिक मांग है।

13. इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह रिट याचिका, बिना किसी योग्यता के होने के कारण, खारिज कर दी जाए।

14. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अधिनियम की अनुसूची (1) की मद संख्या 9 के तहत, सार्वजनिक मांग के रूप में किसी भी सरकारी कर्मचारी को अन्य बातों के साथ-साथ देय धन की वसूली के लिए, *अनिवार्य शर्त* यह है कि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को एक लिखित उपकरण द्वारा सहमत होना चाहिए कि यह वसूली योग्य होगा एक सार्वजनिक मांग है। अनुबंध की शर्त के खंड 2 और 3 सहित रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता और उत्तरदाता सं. 5 के बीच कोई लिखित समझौता नहीं है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता ने सहमति व्यक्त की है कि भुगतान, यदि कोई हो, उसके द्वारा उत्तरदाता सं. 5 या सरकार के किसी भी सेवक को किया जाना है, सार्वजनिक धन के रूप में वसूल किया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तरदाता सं. 5 के दावे को सार्वजनिक मांग के रूप में नहीं माना जा सकता है, जैसा कि उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 की मद संख्या 9 के साथ पठित धारा 3 (6) के तहत परिभाषित किया गया है।

15. जहां तक **मेसर्स अजय भगत बनाम झारखंड राज्य और अन्य (सुप्रा)** के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के फैसले का संबंध है, उस मामले के विपरीत, इस मामले में याचिकाकर्ता यह स्वीकार नहीं करता है कि उसे अग्रिम के रूप में धन प्राप्त हुआ है, बल्कि याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके द्वारा प्राप्त धन, (क) क्या यह सच है कि सरकार चालू बिलों के विरुद्ध है जिसे किसी भी प्रकार से अग्रिम नहीं माना जा सकता है। इसलिए, इस मामले के तथ्य **मेसर्स अजय भगत बनाम झारखंड राज्य और अन्य (सुप्रा)** के

मामले से अलग हैं। इसलिए, उस मामले का अनुपात इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

16. ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, चूंकि उत्तरदाता सं. 5 द्वारा किया गया दावा सार्वजनिक मांग नहीं है, इसलिए इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि बिहार और उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1914 (झारखंड राज्य द्वारा अपनाया गया) के प्रावधानों के तहत उत्तरदाता सं. 5 के आवेदन पर उत्तरदाता सं. 6 द्वारा शुरू की गई कार्यवाही सर्टिफिकेट ऑफिसर के कोर्ट के सर्टिफिकेट केस संख्या 1242 /2016-17 के तहत, पलामू के गढ़वा मुरीसेमर खंड के एनएच-75 के किमी 235 में तेरकी नाला पर पुल के निर्माण के कार्य के लिए करार संख्या 4 एफ 2/2008-09, और 1 एफ 2 / 2011-12 के संबंध में कथित बकायों की वसूली के लिए कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

17. तदनुसार, बिहार और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (झारखंड राज्य द्वारा अपनाया गया) के प्रावधानों के तहत उत्तरदाता सं. 5 के आवेदन पर उत्तरदाता सं. 6 द्वारा शुरू की गई पूरी कार्यवाही समझौते संख्या 4 एफ 2 / 2008-09 और 1 एफ 2 / 2011-12 के संबंध में कथित बकाया राशि की वसूली के लिए प्रमाण पत्र अधिकारी, पलामू की अदालत के सर्टिफिकेट केस संख्या 1242 /2016-17 के तहत गढ़वा नगर मुरीसेमर खंड के एन एच 75 मे 235 किमी में तेरकी नाला पर पुल को रद्द कर दिया गया है और अलग रख दिया गया है।

18. परिणाम में, इस रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

19. राज्य कानूनी रूप से अनुमत होने पर किसी अन्य प्रणाली में अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए स्वतंत्र है।

**(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाo.)**

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 21 मार्च, 2024
ए. एफ. आर/ अनिमेष

**<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया</u>**।